

[Shri Syed Sibte Razi]

to the District Elections Officers and their staff are:

"If you happen to be returning officer in any Union Territory, you shall be responsible for the safe custody of the packets containing election papers referred to in sub-rule (2) of rule 92 of the Conduct of Elections Rules, 1961.

These are:

(1) The packets of unused ballot papers with counterfoils attached thereto;

(2) the packets of used ballot papers—which concerns us here—whether valid, tendered or rejected. This also includes packets in which covers containing postal ballot papers received late are kept."

(3) the packets of the counterfoils of used ballot papers;

(4) the packets of the marked copy of the electoral roll; and so on.

"According to Commission's direction, the District Election Officer will have to keep the above mentioned steel trunks containing papers referred to at items (1) to (5) under double lock in the District Treasury or Sub-Treasury, as may be convenient and the other box containing papers referred to at item (6) in his own safe custody."

"One set of keys of the sealed steel trunks kept in the Treasury/Sub-Treasury will be entrusted to the Treasury Officer or an officer in the Treasury authorised in the Treasury Code. The other set of keys will be kept by the District Election Officer himself or by a senior officer nominated by him."

or, so much of precaution has been taken in this connection and it has

also been clearly stipulated as to how to destroy the used ballot papers. And I quote from The Handbook For Returning Officers, page 112—Direction under Rule 94(b).—(i)

"The sealed packets of used ballot papers (except the packets containing the counterfoils of used ballot papers) whether valid, tendered or rejected, the packets of the marked copies of the electoral roll and the packets of declarations by electors and the attestation of their signatures, which are contained in the sealed steel trunks under the double lock and kept in the Treasury should be retained for a period of one year after the completion of the election and then destroyed."

If the news covered by a leading paper is correct, I think the basic objective of secrecy of ballot papers and choice of a voter has not been maintained and I request the Government that a thorough enquiry be made in such instances because it may lose the confidence in general voters and it may, in future, harm the very set-up of our democracy. Thank you.

REFERENCE TO THE REPORTED FREQUENT POWER BREAK DOWN IN KANPUR CAUSING LOSS TO INDUSTRIES.

श्री नरेन्द्र सिंह (उत्तर प्रदेश) :

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का और सरकार का ध्यान जो कानपुर में और उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति की, जो स्थिति है, उस की ओर दिलाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर, हमारे कानपुर में बिजली के बारे में कहा जाता है कि वह आँख मिचौनी करती है। आई पांच सात मिनट के लिए, उसके बाद बिजली गायब हो जाती है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि कानपुर नगर जो एक बहुत बड़ा औद्योगिक नगर है, जिसकी करीब 20 लाख की आबादी है, उसमें उद्योग बन्द होने

जा रहे हैं। छोटे-छोटे कारखाने बन्द होने जा रहे हैं। तमाम मजदूर परेशान हो रहे हैं और उत्पादन में बहुत बड़ी क्षति हो रही है। मान्यवर, एक तरफ तो उत्पादन में क्षति हो रही है, दूसरी ओर इन दिनों विद्यार्थियों के इम्तिहान हो रहे हैं, हायर सैकेन्डरी के, इन्टर-मिडिएट के और डिग्री कालेज के और यूनिवर्सिटीज के भी इम्तिहान 15 मई से होने को हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने में बड़ी कठिनाई हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है। इधर देहातों में, गावों के इलाकों में थ्रेशिंग का काम बड़ी तेजी से होना है, लेकिन बिजली नहीं है। किसान परेशान है। बिजली न मिलने के कारण किसानों का दिल बहुत दुखी है। वे अपनी फसल को निकाल नहीं पा रहे हैं।

मान्यवर, सन् 1982 का वर्ष उत्पादकता वर्ष है। इस वर्ष में बिजली की कमी से बड़ी कठिनाई हो रही है। अगर इस प्रकार से बिजली की कमी रही तो जो हमारा उद्देश्य है, जो हमने उत्पादकता का वर्ष घोषित किया है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसमें जो कानपुर का स्थिति है उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कानपुर में जो स्थिति हुई उसमें अधिकारियों की कितनी लापरवाही है, इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। 23 अप्रैल को इन्टर-कनेक्टर में खराबी आ गई। लेकिन 24 अप्रैल तक अधिकारियों की तरफ से, केसा विभाग की तरफ से और बिजली विभाग की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसकी फिकर बिल्कुल नहीं की गई कि इसमें जो डिफेक्ट है, फाल्ट है उनको दूर करने के लिए तुरन्त कुछ किया जाना चाहिए। जो लोग उनसे शिकायत करने जाते हैं मान्यवर, तो

अधिकारियों का रवैया यह है कि तसल्ली देने के बजाय वे उनको रूखा जवाब देते हैं, बड़ी धृष्टता से पेश आते हैं। वह यह समझते ही नहीं है कि उनकी कोई जिम्मेदारी है। मान्यवर, इस संबंध में तमाम समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं और कितनी लापरवाही और किस बेफिक्री के साथ ये अधिकारी लोगों को जवाब देते हैं इसका मैं एक नमूना आपके सामने पेश करना चाहता हूँ :—

“रिवरसाइड पावर हाउस के दो इंटरकनेक्टरों में से एक में फाल्ट आ जाने के कारण नगर की बिजली आपूर्ति पिछले तीन दिनों से बुरी तरह प्रभावित है। कैसा द्वारा यह स्थिति अभी दो दिन और चलने की सम्भावना व्यक्त की गयी है। अनेक औद्योगिक इकाइयों में कार्य ठप्प होने की स्थिति आ गई है तथा व्यवसाय चौपट हो रहा है।

एक इंटर कनेक्टर में आजाद नगर के पास फाल्ट आ जाने के कारण विद्युत आपूर्ति यकायक आधी रह गयी।

बताया जाता है कि कानपुर को 75 मैगावाट बिजली की आवश्यकता है जिसमें से उसे केवल 50 मैगावाट बिजली से ही काम चलाना पड़ रहा था। एक इंटरकनेक्टर में फाल्ट होने से अब कानपुर को केवल 25 मैगावाट बिजली ही मिल रही है। परिणामस्वरूप नगर के विभिन्न क्षेत्रों में रुक-रुक कर विद्युत कटौती क गई है। इंटर कनेक्टर में यह गड़बड़ गत गुरुवार को दोपहर 3 बजे से हुई लेकिन केसा विभाग ने इस मामले में कोई तत्परता नहीं दिखाई।

[श्री नरेन्द्र सिंह]

स्वयं केसा के एकजीक्यूटिव इंजीनियर श्री एम० एस० सिद्दीकी ने इस बात को स्वीकार किया कि इंटर कनेक्टर में गड़बड़ी की खोजबीन कल शुक्रवार से ही शुरू की गई । इंटर कनेक्टर में फाल्ट खोज निकालने के लिए केसा विभाग ने आजाद नगर में बी० एस० एस० डी० कालेज में पीछे लगभग 5-6 स्थानों में खुदाई की तब होस्टल के निकट एक स्थान पर आज दोपहर बाद फाल्ट मिला ।"

मान्यवर, यह स्थिति है । केसा के अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे हैं । मान्यवर, देश में जो बिजली का उत्पादन है, उसमें वृद्धि हुई है । 1979-80 में 16.8 प्रतिशत कमी बिजली की देश में थी और 1981-82 में यह 10.1 प्रतिशत ही कमी रह गई है बिजली के उत्पादन में । लेकिन व्यवस्था में गड़बड़ी है । एक तरफ बिली के चार्ज बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ बिजली की सप्लाय खराब हो रही है और बिजली की सप्लाय नहीं होती । मान्यवर, मेरा सरकार से यह निवेदन है इस सदन के जरिए से कि बिजली विभाग के अधिकारी जिन्होंने लापरवाही की है, जो लापरवाही बरतते हैं, इस तरह से देश के साथ खिलवाड़ करते हैं, इस देश के किसानों के साथ, गरीबों के साथ मजदूर के साथ, और इस देश के उत्पादन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए और सरकार को इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए । ज

REFERENCE TO THE DIFFICULTIES
BEING FACED BY FARMERS IN
DIFFERENT PARTS OF THE COUN-
TRY DUE TO POWER SHORTAGE

श्री हुषम देव नारायण यादव

(बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी श्री नरेन्द्र सिंह जी जिस विषय को उठा रहे थे मैंने भी उस पर स्पेशल मेशन दिया था । अब मेरी प्रार्थना यह होगी कि जब तक केन्द्रीय सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ इस विद्युत की समस्या का समाधान नहीं करना चाहेगी तब तक इस समस्या का समाधान देश में हो नहीं सकता । . . . (व्यवधान)

इसको राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया है । मैं आपसे निवेदन यह करूंगा कि हमारे बिहार में जो कांटी थर्मल पावर स्टेशन बन रहा था, वह जिस समय पर पूरा होना चाहिये था वह इसलिए उस समय पर पूरा नहीं हो रहा है चूंकि वहां पर काम करने के लिए और कारखाने की मशीनों के लिए बिजली चाहिये जो नहीं मिल रही है । बिजली उत्पादन के लिए जो कारखाने बन रहे हैं उन में विलम्ब इसलिए हो रहा है कि उनको बिजली नहीं मिल रही है । यह बिजली क्यों नहीं मिल रही है । बिजली वालों का कहना है कि कोयला नहीं मिल रहा है, कोयले वालों का कहना है कि रेल वैगन नहीं मिल रहे हैं, रेल वैगन वालों का कहना है कि वैगन वापस चले जा रहे हैं । अब इस झूठ के महासमुद्र में यह सम्पूर्ण देश के उद्योग और सम्पूर्ण देश के किसान मारे जा रहे हैं । उद्योग और खासकर जो छोटे छोटे उद्योग हमारे यहां हैं उनकी दुर्गति हो रही है । अभी श्री नरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि इससे किसानों की सबसे ज्यादा दुर्गति हो रही है । एक तरफ नीचे सरकार की उनके ऊपर दृष्टि है और ऊपर इन्द्र महाराज की कुदृष्टि है । बीच में पानी पड़ जाता है, बिजली नहीं मिलती । गेहूं के जो खलिहान किसानों के हैं वे सड़ रहे हैं और इसके लिए सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का मुआवजा और क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है । किसान यहां भी मारा जा रहा है । दूसरी तरफ अगर फसल बसल लगाने की बात हो तो हालत यह है कि लोग जाते हैं अपनी बोरिंग पर . . . बैठे रहते हैं और हाथ में